year 1996-97. NABARD also proposes to sanction credit limits of the order of Rs. 7700 crores to cooperative banks and Regional Rural Banks for their short term operations (both for Seasonal Agricultural Operations and other purposes) as against limits of Rs. 6992 crores sanctioned during 1996-97. As far as RIDF is concerned, it is expected that NABARD will sanction loans to State Governments to the full extent for rural infrastructure projects under RIDF-III which has a corpus of Rs. 2500 crores. The State/Union Territory-wise details of allocations of refinance under Investment credit (Schematic Lending) and Short term credit (Seasonal Agricultural Operations) have already been firmed up by NABARD and are indicated at *Annexure. [See* Appendix 180, Annexure No. 89]. The Committee disbursements under RIDF-I & II together with normative allocations under RIDF-III, State-wise are also furnished in the same annexure.

As reported by NABARD, 64 projects located in 15 districts in Maharashtra have been provided refinance support amounting to approximately Rs. 13 crores under its Investment Credit operations during the period December, 1996 March, 1997. Further, during this period, 108 projects have also been sanctioned under RIDF in 17 districts of the State, involving a total loan of Rs. 231. 66 crores. NABARD has further reported that 38 projects in the State are awaiting clearance under Investment Credit (Schematic Lending) involving a refinance amount of Rs. 38.17 crores. Under RIDF-III a normative allocation of Rs. 192.45 crores has been made in favour of the State. The proposals in this regard are being firmed up.

Record Power Generation at Narora Atomic Power Station

*564. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Narora Atomic Power Station has produced record power during January and February, 1997;

(b) whether the load factors were as high as 103.5% in January, 1997; and

(c) if so, what were the reasons for this phenomenal success?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The load factor for Unit-1 of Narora Atomic Power Station was 103.5% and that for Unit-2 was 101.2% in the month of January, 1997.

(c) Concerted efforts have been made to improve the performance and reliability of the operating nuclear power plants and as a result the performance has improved over the past two years.The measures taken to improve performance of nuclear power plants include modifications carried out on the turbo generators supplied by BHEL, strengthening of condition monitoring and preventive and predictive maintenance, improving outage management, intensive training for maintenance and operating staff, effective co-ordination with Regional Electricity Board to improve frequency control of the grid and centralisation of decision making to enable prompt action at the operating stations. These efforts have enabled Narora Atomic Power Station to operate at maximum efficiency.

मध्य प्रदेश में छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां

566. **श्री दलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में शुरू किया गया छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास कार्यक्रम अभी भी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए कस्बों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य के नरसिंहगढ़, जशपुर नगर और विदिशा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे संबंधित दिशानिर्देशों में कोई संशोधन/ परिवर्तन किया गिया है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जी हां।

(ख) स्कीम की शुरुआत से 1996-97 तक मध्य प्रदेश के 72 कस्बों को छोटे व मझोले, कस्बों के एकीकृत विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है (जिलावार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) विदिशा शहर को 1990-91 के दौरान संशोधन-पूर्व आई डी एस एम टी स्कीम के दिशा निर्देश के तहत इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था और उसे केन्द्रीय सहायता (ऋण) की प्रथम किस्त के रूप में 10 लाख रु० दिये गए थे। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता राज्य अंश में से अब तक 12.71 लाख रु० के व्यय की सूचना दी है। विदिशा में इस कार्यक्रम की कम प्रगति का मुख्य कारण यह है कि संशोधन-पूर्व दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सहायता राशि सहित समूची राशि ऋण के रूप में थी। जहां तक नरसिंह गढ़ का सवाल है, स्कीम के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत उसे 27 लाख रु० की राशि मार्च, 1996 में अनुदान के रूप में दी गई थी। राज्य सरकार ने वहां पर अब तक खर्च की न तो सूचना दी है और न आगे की केन्द्रीय सहायता का कोई अनुरोध किया गया है। इसका कारण व्यावहारिक स्तर पर आने वाली कार्यान्वयन कठिनाइयां हैं। जसपुर शहर के लिए इस स्कीम के तहत राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। छोटे व मझोले कस्बों के एकीकृत विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के तहत कस्बों को लेने, उनके दायरा निर्धारण, परियोजनाओं के चयन, अनुमोदन और कार्यान्वयन के दायित्व राज्य सरकारों को सौंपे गये हैं।

(ङ) और (च) स्कीम को अधिक कारगर बनाने के लिए उसके कार्यान्वयन के दिशा निर्देशों में पिछला संशोधन अगस्त 1995 में किया गया था। ताकि संशोधित स्कीम 3 से 5 लाख की आबादी वाले कस्बों तक बढ़ा दिया गया है, केन्द्रीय और राज्य हिस्से की राशि की ऋण से अनुदान में बदला गया है और उसकी अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों पर ऋण भार को कम करने के लिए संस्थाओं से जुटाये जाने वाली राशि की मात्रा, प्रत्येक चुनींदा शहर की आबादी के आधार पर परियोजना लागत के 40-70% से घटाकर 20-40% कर दी गई है। स्कीम के दिशा-निर्देशों में संशोधन का मुख्य कारण यह था कि पूर्व-वित्त व्यवस्था पद्धति में केन्द्रीय और राज्य हिस्से की राशि अंश ऋण के रूप में होती थी और संस्थागत वित्त घटक का प्रतिशत भी काफी अधिक था।

विवरण

छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास की स्कीम में शामिल मध्य प्रदेश के कस्बों की जिला-बार संख्या (1979-80 से 1996-97)

क्रम संख्या	जिले का नाम	शामिल किए गए शहरों की संख्या
1.	बालाघाट	1
2.	बिलासपुर	4
3.	बस्तर	2
4.	बेतल	2
5.	भिन्ड	1
6.	भोपाल	1
7.	छिन्दवाडा	3
8.	छतरपुर	2
9.	देवास	1
10.	दुर्ग भिलाई दुर्ग	2
11.	दामोह	1
12.	धार	1
13.	दतिया	1
14.	पूर्विनिवासखंडवा	2
15.	गूना	2
16.	ग्वालियर	1
17.	होशंगाबाद	4
18.	इंदौर	1
19.	जबलपुर	2
20.	खरगोन	2
21.	इंदौर	1
22.	मुरैना	2

23.	मंदसौर	3
24.	मांडला	1
25.	नरसिंहपुर	2
26.	पन्ना	2
27.	राजनंद गांव	3
28.	रीवा	1
29.	रतलाम	2
30.	रायतेन	1
31.	रायगढ़	1
32.	राजगढ़	3
33.	सिदूर्दी	2
34.	शिवपुरी	1
35.	सतना	4
36.	सादर	1
37.	शहडोल	2
38.	शिहोर	1
39.	टिकमगढ़	1
40.	विदिशा	2
	योग	72

Target of Nuclear Power Generation

*567. SMT. JAYANTI PATNAIK: Will the PRIME MINISTER be pelased to State:

(a) the targets fixed for the generation of nuclear power by the turn of the century;

(b) the steps taken to achieve the target;

(c) whether generation of nuclear power is proposed to be privatised;

(d) if so, the steps taken thereon; and

(e) what other steps are being taken to increase nuclear pwoer generation so that the target set for by the turn of the century is achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S VENUGOPALACHARI): (a) and (b) It is proposed to achieve an installed nuclear power generation capacity of 2720 MW with the additional of 880 MWe to the installed capacity by the turn of the century by commissioning of the ongoing projects viz. Kaiga 1 & 2 and Rajasthan Atmoic Power Project 3 & 4 during 1998-99.

(c) and (d) Government of India are open to specific offers for participation by private firms, Indian or foreign, in the nuclear power sector. Such offers, when received, have to be considered on the basis of technical suitability, economic attractiveness and conditions attached thereto.

(e) Does not arise.

Functioning of RBI's Regional Office at Bhopal

*569. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that RBI's Regional Office was set-up in Bhopal in 1972;

(b) whether the main purpose of this regional office was to help and assist the State Government in clearance of various cheques and deposits;

(c) if so, whether this office is not functioning as per requirements and purpose for which this was set up;

(d) whether the Madhya Pradesh Government has to depend on the Nagpur Office on Public Accounts Department (PAD), Deposits Accounts Department (DAD) and Public Debt Office (PDO);

(e) if so, whether Government are considering to make the RBI's Branch at Bhopal purposeful; and

(f) if so, the directives issued in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir. RBI's Bhopal office was set up in 1972.

(b) to (d) According to Reserve Bank of India the main purpose of setting up of